दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति येओल से ढाई घंटे तक हुई पूछताछ, बयान देने से इनकार

सियोल

दक्षिण कोरिया के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) के अधिकारियों ने सुबह हिरासत में लिये गए राष्ट्रपति यून सुक येओल से पूछताछ शुरू कर दी। येओल को राष्ट्रपति आवास से हिरासत में लेने के बाद ग्योंगगी प्रांत के ग्वाचेओन स्थित सीआईओ मुख्यालय ले जाया गया। यहां ढाई घंटे तक उनसे पूछताछ की गई।

सीआईओ के डिप्टी प्रमुख ली जे-सेउंग के नेतृत्व में अधिकारियों ने सुबह करीब 11 बजे यून सुक येओल से पूछताछ शुरू की। इस दौरान येओल के वकील भी मौजूद रहे।

येओल से पूछताछ मुख्यत: उनकी मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा पर केंद्रित है। यह घोषणा येओल ने तीन दिसंबर की रात की थी। इस बीच विपक्ष के तेवर देख यह घोषणा वापस ले ली गई। विपक्ष ने मोर्चाबंदी कर नेशनल असेंबली की पूर्ण बैठक आहूत कर येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इस पर मतदान हुआ। मतदान में राष्ट्रपति को तगड़ा झटका लगा और महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद इसे संवैधानिक अदालत भेजा गया। संवैधानिक अदालत में मंगलवार को इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है।

यून सुक येओल हिरासत में लिये जाने वाले पहले मौजूदा कोरियाई राष्ट्रपति हैं। जांच अधिकारियों को 48 घंटों के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि हिरासत में पूछताछ जारी रखने के लिए औपचारिक गिरफ्तारी वारंट दायर किया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए। सीआईओ ने सुबह 10:33 बजे हिरासत वारंट निष्पादित किया।

न्यूज ब्रीफ

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चार आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के सामान्य क्षेत्र स्पिनवाम में चार आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने इसकी पुष्टि की। आईएसपीआर ने कहा कि सुरक्षाबलों को यह कामयाबी 14/15 जनवरी की रात खुफिया आधारित अभियान में मिली। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को घेरकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस दौरान चार आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के ठिकाने से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने प्रांत के टैंक और खैबर जिलों में दो खुफिया आधारित अभियानों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया था।

काठमांडू से चीन के नागरिक का अपहरण करने वाले महाराष्ट्र के चार युवक नेपाल पुलिस की हिरासत में

काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू के सबसे व्यस्ततम पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल से चीन के एक नागरिक का अपहरण कर भारत के तरफ ले जाने का प्रयास करते हुए चार भारतीय युवकों को नेपाल पुलिस ने भारतीय सीमा से 90 किलोमीटर पहले ही दबोच लिया। काठमांडू घूमने आए महाराष्ट्र के चार युवक पिछले तीन दिन से ठमेल के एक होटल में ठहरे हुए थे। इस दौरान एक चीनी नागरिक के साथ किसी बात पर अनबन होने के बाद इन युवकों ने मंगलवार देररात उसे अगवा कर अपनी कार से ले जाने की कोशिश की। काठमांडू क्राइम ब्रांच के एसएसपी सानू थापा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे ठमेल एरिया से यह जानकारी मिली। इसके बाद काठमांडू पुलिस सक्रिय हुई और सीसीटीवी के जरिए उस भारतीय नंबर प्लेट की गाड़ी (स्कॉर्पियो) के बारे में पता लगाया जिसमें चीनी नागरिक को जबरन बैठाया गया था। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए भारतीय सीमा से करीब 90 किलोमीटर पहले हेटौडा के पास रहे भीमफेदी के जंगल में इस गाड़ी (एमएच16डीजी 4904) को घेर लिया। पुलिस ने चीनी नागरिक और चारों आरोपितों को दबोच लिया। नेपाल पुलिस के अनुसार आरोपित युवकों की पहचान सातारा जिला निवासी 32 वर्षीय आशुतोष दत्तात्रेय, अहमदनगर के 30 वर्षीय अमोल करमाटे, 33 वर्षीय अमोल श्रीसत और गाड़ी चालक 40 वर्षीय अफसर शेख के रूप में की गई है। पुलिस ने अपहृत किए गए चीनी नागरिक के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है।

नेपाल ने हमास के कब्जे से छात्र की रिहाई के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए

काठमांडू। नेपाल ने हमास के कब्जे से नेपाली छात्र विपीन जोशी की रिहाई को लेकर कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा ने कतर और इजराइल के विदेश राज्यमंत्री से टेलीफोन पर वार्ता की है। हमास ने कुछ बंधकों की रिहाई की घोषणा की है। इसमें नेपाली छात्र विपीन जोशी का नाम नहीं है। विदेशमंत्री डॉ. राणा ने मंगलवार को पहले कतर के विदेश राज्यमंत्री डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल-खुलाइफी से टेलीफोन वार्ता कर मदद मांगी। खुलाइफी हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। विदेशमंत्री ने एक्स पर कहा है कि कतर के विदेश राज्यमंत्री ने नेपाली छात्र के रिहाई कराने का आश्वासन दिया है। मंगलवार देररात विदेशमंत्री राणा ने इजराइल के विदेश राज्यमंत्री गिडियन सार से भी टेलीफोन वार्ता की। राणा ने एक्स में कहा कि इजराइल नेपाली छात्र विपीन जोशी की रिहाई के लिए पहल कर रहा है।

बाइडेन ने अमेरिका में एआई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर एक महत्वपूर्ण आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए अमेरिका में उन्नत (एडवांस्ड) एआई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे, जैसे बड़े पैमाने पर डाटा केंद्र और नई स्वच्छ उर्जा सुविधाएं, का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि रक्षा और उर्जा विभाग उन स्थानों की पहचान करेंगें, जहां निजी कंपनियां एआई डाटा केंद्र बना सकें। इसके अलावा, इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अपने डाटा केंद्र के लिए पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करें।

एक बयान में, बिडेन ने कहा कि एआई का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और अगर जिम्मेदारी से इसका उपयोग किया जाए तो अमेरिकियों के जीवन में सुधार करने की भारी क्षमता होगी। इससे बीमारियों का इलाज करने से लेकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर समुदायों को सुरक्षित रखने तक का काम किया जा सकेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि %एआई के मुद्दे पर हम अपनी बढ़त को हल्के में नहीं ले सकते। जब भविष्य को परिभाषित करने वाली प्रौद्योगिकी की बात आती है तो हम अमेरिका को कमजोर नहीं होने देंगे। न ही हमें महत्वपूर्ण पर्यावरण मानकों और स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की रक्षा के लिए हमारे साझा प्रयासों का त्याग करना चाहिए।

नए नियमों के तहत, रक्षा और ऊर्जा विभाग प्रत्येक कम से कम तीन साइटों की पहचान करेंगे जहां निजी क्षेत्र एआई डेटा केंद्र बना सकते हैं। वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि एजेंसियां उन संघीय साइटों पर एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धी अनुरोध चलाएंगी।

वियतनाम और रूस ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने के समझौते पर किए हस्ताक्षर

हनोई

रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन की दो दिवसीय हनोई यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को वियतनाम और रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बढ़ती लागत और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 2016 में दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण बंद करने के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपनी परमाणु ऊर्जा योजनाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि इससे वर्ष 2050 तक उसे ऊर्जा-पर्याप्त बनने और अतिरिक्त ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस समझौते पर रूस की सरकारी स्वामित्व वाली परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम और वियतनाम की सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता ईवीएन के बीच हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मिशुस्टिन ने अपने समकक्ष फाम मिन्ह चिन्ह के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख टू लैम और वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान से मुलाकात की। मिशुस्टिन ने कहा, वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में रूस का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। हम आपके साथ रूस और वियतनाम के बीच सहयोग की एक व्यापक योजना पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं, जो 2030 तक चलेगी। अगले दिन बुधवार को वो राष्ट्रपति लुओंग कुओंग से भी मुलाकात करेंगे।

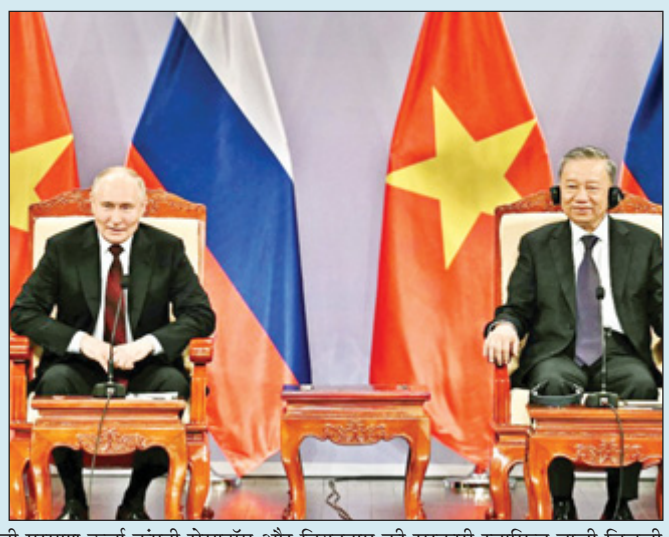

नेपाल-भारत जेटीटी और जेडब्ल्यूजी की बैठक 21-22 जनवरी को नई दिल्ली में

काठमांडू

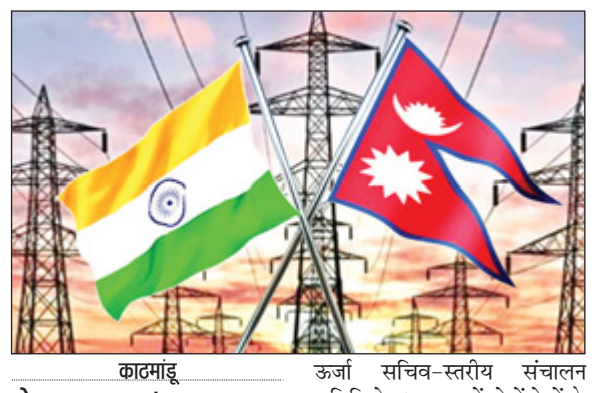

नेपाल-भारत संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीटी) और संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की ऊर्जा क्षेत्र पर बैठक 21 और 22 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। हर 6 महीने के अंतराल पर होने वाली बैठक इस बार एक वर्ष के बाद होने जा रही है। इससे पहले सह सचिव के नेतृत्व वाली जेडब्ल्यूजी की बैठक पिछले साल 2 जनवरी और सचिव के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक समिति (जेएससी) की बैठक 3 जनवरी, 2024 को हुई थी।

ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ प्रबल अधिकारी ने बताया कि मौजूदा बैठक में नेपाल और भारत के बीच बनने वाली दो हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण और निवेश प्रारूप को अंतिम रूप देने पर चर्चा की जाएगी और संभव हुआ तो इस पर समझौते पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है।

पिछले साल 21 दिसंबर को चितवन (नेपाल) में और भारत की ऊर्जा सचिव-स्तरीय संचालन समिति ने 2027/28 में दोनों देशों के बीच तीसरी सबसे बड़ी इनरुवा-पूर्णिया 400 केवी अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी।

इसी प्रकार समान क्षमता की एक और अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन, लमकी (डोडोधारा) - बरेली ट्रांसमिशन लाइन को 2028/29 में पूरा करने पर भी सहमति हो चुकी है। हालांकि, उस बैठक में इन दोनों ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण प्रारूप और निवेश प्रारूप पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी।

बैठक में नेपाल ने इन दोनों ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण बुटवल-गोरखपुर 400 केवी अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के समान तरीके से करने का प्रस्ताव रखा। नेपाल की ओर ट्रांसमिशन लाइन का हिस्सा नेपाल द्वारा स्वयं बनाया जा रहा है, जबकि भारत की ओर वाला हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरण और एक कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है जिसके पास भारत की ट्रांसमिशन ग्रिड कंपनी के आधे शेयर हैं। नेपाल की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है कि 25 साल के कार्यान्वयन और ट्रांसमिशन सेवा समझौते (आईटीएसए) के तहत बिजली प्राधिकरण इस ट्रांसमिशन लाइन के पूरे उपयोग और किराये (व्हीलिंग चार्ज) का भुगतान करेगा। इस बात पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।

बमबारी

गाजा में इजरायली बमबारी के कारण ध्वस्त हुए टेंटों के पास खड़े हुए फिलिस्तीनी लोग।

प्रचण्ड ने कहा-अब ओली सरकार की आयु अधिक नहीं

काठमांडू

नेपाल के विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी ओली और उनकी सरकार की आलोचना की है। प्रमुख विपक्षी नेता पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड ने कहा कि अब ओली सरकार की आयु अधिक नहीं है।

माओवादी संसदीय दल के कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में माओवादी के अलावा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी और आम जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही। बैठक में ओली सरकार द्वारा संसद की बैठक नहीं बुलाने और अध्यादेश के माध्यम से शासन करने का आरोप लगाया गया। साथ ही सरकार के 6 महीना पूरा होने पर भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होने का आरोप भी लगाया गया। प्रचण्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली के रवैये से सत्तारूढ़ दलों में असंतुष्टि चरम पर पहुंच गई है। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेताओं का सरकार के विरोध में सार्वजनिक बयान आ रहा है। उसको देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं होने का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। प्रचंड ने पत्रकारों को कहा कि ओली सरकार की आयु अब अधिक दिनों की नहीं बची है। ओली सरकार को अपदस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचंड ने कहा कि किसी भी समय नेपाली कांग्रेस ओली सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। प्रचण्ड ने कहा कि नए सत्ता गठबंधन के लिए विपक्षी दलों के तरफ से नेपाली कांग्रेस को सरकार के नेतृत्व का खुला ऑफर दे दिया गया है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ओली सरकार से समर्थन वापस ले लेगी उसी दिन नया गठबंधन अस्तित्व में आ जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ओली के साथ फिर से हाथ मिलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जो गलती वो पहले दो बार कर चुके हैं वो इस बार नहीं करने वाले हैं।

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जिया अनाथालय ट्रस्ट मामले में खालिदा को बरी किया

ढाका

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित जिया अनाथालय ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद रेफअत अहमद ने सुबह करीब पौने नौ बजे फैसला सुनाया।

बांग्लादेश के समाचार पत्र प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 79 वर्षीय खालिदा जिया की अपील की समीक्षा के बाद प्रधान न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने खालिदा जिया, उनके पुत्र तारिक रहमान सहित सभी दोषियों को बरी कर दिया। तारिक बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

खालिदा जिया के वकील जॉयनुल आबेदीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2018 को खालिदा जिया की ट्रायल कोर्ट की पांच साल की कैद की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। 14 मार्च, 2019 को खालिदा जिया ने फैसले के खिलाफ दो अलग-अलग याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने 11 नवंबर को खालिदा जिया की याचिका को मंजूर करते हुए फैसले पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने तीन जुलाई, 2008 को जया अनाथालय ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था। इसमें खालिदा जिया पर एक विदेशी बैंक के माध्यम से अनाथों के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त 21 मिलियन टका से अधिक का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। आठ फरवरी, 2018 को विशेष न्यायाधीश कोर्ट-5 ने फैसला सुनाया और खालिदा जिया को 5 साल की सजा सुनाई। उनके बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, पूर्व संसद सदस्य काजी सलीमुल हक कमाल, पूर्व प्रमुख सचिव कमालुद्दीन सिद्दीकी, व्यवसायी शरफुद्दीन अहमद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। खालिदा जिया ने 2018 में ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने खालिदा जिया की अपील खारिज कर उनकी पांच साल कैद की सजा को भी बढ़ाकर 10 साल कर दिया था।

एलन मस्क और जुकरबर्ग ट्रम्प के शपथ ग्रहण में एक साथ आएंगे नजर

वाशिंगटन। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग जो एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्विता के जाने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ बैठे नजर आ सकते हैं। दोनों के बीच कई मुद्दों पर असहमतियां हैं जैसे कि एआई, सोशल मीडिया नीतियां आदि को लेकर। मस्क ने पहले जुकरबर्ग के साथ एक पिंजरे की लड़ाई की घोषणा की थी और भाषण पर उनके दृष्टिकोण की आलोचना की थी। वहीं एलन मस्क के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं हैं जबकि मार्क जुकरबर्ग एक्स पर उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अब ट्रम्प के उद्घाटन समारोह ने इन दोनों तकनीकी अरबपतियों को एक साथ लाने का काम किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच के मतभेदों के बावजूद यह उनके रिश्ते में बदलाव का संकेत हो सकता है। इस बीच अमेरिका एजेंसी एसईसी ने मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।